भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2275
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तें

2275. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके सरकारी कार्य-निर्वहन के भाग के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार टीए को बहाल करने के केरल के अनुरोध पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केन्द्र सरकार एपीआईपी 2025-2026 द्वारा अनुमोदित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मानदेय को जारी करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या केन्द्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ स्थानीय समुदाय से आई मानद कार्यकर्त्रियां हैं जो स्वेच्छा से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ प्रदान

करके स्थानीय समुदाय की सहायता करती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह राशि केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन और टॉप-अप भी दे रहे हैं, जो राज्यवार भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए अतिरिक्त टॉप-अप का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से समर्थ बनाया गया है। पोषण ट्रैकर जो मोबाइल फोन एप्लिकेशन है, में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल किया गया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही वे आंगनवाड़ियों में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय (रियल टाईम) निगरानी कर पाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) पदोन्नति : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, बशर्ते वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(ii) अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात/गर्भस्राव पर एक बार 45 दिनों का सवैतनिक अवकाश।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करें कि वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित करवाएं। यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं : 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु) और 18-59 वर्ष के आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज दी गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी नीति एवं आयोजना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि योजना के दैनिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

*****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तें " विषय पर दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2275 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप का ब्यौरा:

(रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को भुगतान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप	आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भुगतान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप
1	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
2	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
3	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
4	असम	3,500	1,750
5	बिहार	4,500	2,250
6	चंडीगढ़	3,600	1,800
7	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,500	1,750
9	दिल्ली	6,720	3,360
10	गोवा	15,000 - 23,000	8,500 - 11,500
11	गुजरात	5,500	3,250
12	हरियाणा	10,250	5,650
13	हिमाचल प्रदेश	6,000	3,550
14	जम्मू और कश्मीर	600	300
15	झारखंड	7,000	3,500
16	कर्नाटक	8,000	5,250
17	केरल	8,300	6,800
18	लद्दाख	1,300	650
19	लक्षद्वीप	5,500	4,750
20	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
21	महाराष्ट्र	8,500	5,250
22	मणिपुर	1,000	600
23	मेघालय	3,000	1,000

24	मिजोरम	950	725
25	नागालैंड	शून्य	शून्य
26	ओडिशा	5,500	2,750
27	पुद्दुचेरी	1,950	2,125
28	पंजाब	5,000	2,850
29	राजस्थान	6,061	4,041
30	सिक्किम	7,000	4,500
31	तमिलनाडु	9,780	6,270
32	तेलंगाना	9,150	5,550
33	त्रिपुरा	5,946-3,500	4,218-2,750
34	उत्तर प्रदेश	1,500	750
35	उत्तराखंड	4,800	3,000
36	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550

****